एक रिपोर्ट

"घर घर - भाजपा"

अभियान

15 साल का कांग्रेस का कुशासन

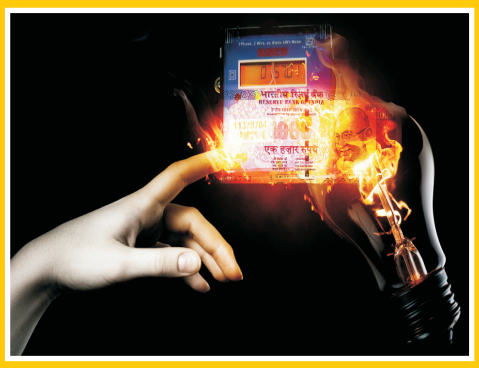

भाजपा लायेगी सुशासन

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश

नई सोच, नई उम्मीद,

प्रस्तावना

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने 'घर–घर भाजपा अभियान' आरंभ किया है। इस अभियान के तहत हम घर–घर जाकर बताएंगे कि 10 साल के मनमोहन सिंह सरकार के कांग्रेस शासन में किस तरह से महंगाई व भ्रष्टाचार बढ़ा है। कई लाख करोड़ की लूटपाट हुई और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई।

इसी तरह से 15 साल की कांग्रेस की शीला सरकार के शासन में कुप्रबंधन और कुशासन के कारण जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट आई और दिल्ली वाले परेशान हो उठे हैं। दिल्ली पेरिस तो नहीं 'स्लम' बन गई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 6 वर्ष में देश में महंगाई और भ्रष्टाचार पर जिस तरह से लगाम कस रखी थी, लोग आज भी याद करते हैं।

इस पुस्तिका के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस हर मोर्चे पर फेल हुई है और भाजपा सत्ता में आएगी तो किस तरह से विकास करेगी और हमारा एजेंडा और दृष्टिकोण क्या होगा। यानी कि हम बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे।

भाजपा ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चुना है। श्री नरेन्द्र मोदी विकास के प्रतीक हैं। भाजपा शासित राज्य गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा ने अच्छी शासन व्यवस्था कायम की है। हम भी दिल्ली को अच्छा सुशासन देंगें। आम नागरिकों को डर नहीं होगा मगर अपराधियों को खौफ होगा; महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, रोजमर्रा की जिन्दगी में एक आम आदमी को परेशानी नहीं आएगी।

हम सिर्फ 5 साल की नहीं, अपितु आने वाले 20 साल की योजनाएं बनाएंगे कि 20 साल बाद दिल्ली को कितनी सड़कों, कितनी बिजली, कितने अस्पताल, कितने स्कूल–कॉलेज, यूनिवर्सिटी और समाज के सभी तबकों के लिए कितने रोजगार के अवसर चाहिए होंगे।

हमारी आपसे अपील है कि एक बार दिल्ली में भाजपा को मौका दें और फिर देखें कि किस तरह से सुशासन आता है। हमारा नारा है –

'भाजपा आएगी,
दिल्ली मुस्कुराएगी।'

विजय गोयल
अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश भाजपा

कैसे करेंगे दिल्ली का विकास
भाजपा का दृष्टिकोण

- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना।
- बेतहाशा बढ़ रही बिजली बिलों की दर में 30 फीसदी कटौती।
- झुग्गी–झोंपड़ी वासियों को पक्के घर मुहैया कराना।
- झुग्गी–झोंपड़ी वालों को मूलभूत सुविधाएं।
- पूरी दिल्ली को पानी की निरंतर और नियमित सप्लाई।
- अवैध कालोनियों में समयबद्ध विकास।
- दिल्ली के गांवों का सम्पूर्ण विकास जिसमें सड़कें, यातायात, बिजली, पानी, शिक्षा और सीवेज आदि सब शामिल होगा।
- सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों पर भर्तियां।
- दिल्ली से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को डीयू में दाखिले के लिए 5 फीसदी अंकों की छूट (चाहे वह किसी भी राज्य का हो)।
- बेहतर पुलिस के जरिए महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर लगाम कसना।
- बच्चों के लिए दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष प्रयास।
- एकीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ।
- देव नदी यमुना की समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से सफाई।
- दिल्ली के पर्यावरण को शुद्ध और बेहतर बनाना।
- प्रदूषण रहित हाईटैक इंडस्ट्री विकसित करना।
- शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों में विशेष इंतजाम ताकि वो भी आम लोगों की तरह हर जगह आसानी से आ–जा सकें।
- रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों को ज्यादा पावर और स्वायत्तता देना।
- लाइसेंस राज को खत्म करना, वैट और अन्य टैक्स प्रक्रियाओं को सरल करना।
- निजी व्यापार में सरकार की कम से कम दखलअंदाजी।
- 'सेवा के अधिकार' और 'ई–गवरनेंस के जरिए प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।
- शहर के समानांतर विकास के लिए सुनियोजित विकास योजनाएं लागू करना।
- ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना।
- अवैध कालोनियों में विकास कार्य तेजी से पूरे करना।
- हर साल एक लाख घर मुहैया कराना ताकि भविष्य में अवैध कालोनियां न पनप सके।

- बीजेपी को अपना ये एजेंडा इसलिए लाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली की कांग्रेस सरकार अपने मूलभूत कर्त्तव्य भी नहीं निभा पायी है। शीला दीक्षित सरकार कहां, कैसे विफल रही, ये भी हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं।

कैसे करेंगे दिल्ली की समस्याओं का समाधान

बिजली

- बिजली के टैरिफ में 30 प्रतिशत कटौती : हम बिजली की दरों में 30 प्रतिशत तक कटौती करेंगे। यह लक्ष्य वितरण कम्पनियों के एकाधिकार में कमी लाकर हासिल किया जाएगा।
- पारदर्शिता लाने–वर्तमान पीपीए की समीक्षा करने के लिए बिजली खरीद समझौते सार्वजनिक किये जाएंगे।
- प्रतिस्पर्धा की शुरूआत : वर्तमान में वितरण कम्पनियों ने मिलकर बिजली वितरण पर एकाधिकार जमा लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जगाएगी जिससे वितरण कम्पनियों के एकाधिकार की समाप्ति होगी तथा बढ़ी हुई टैरिफ दरों में कटौती करने में मदद मिलेगी।
- एकाधिकार की समाप्ति और ओपन एक्सैस सिस्टम की शुरूआत : उपभोक्ता किसी भी कम्पनी की बिजली खरीद सकते हैं, जो सस्ती और निरंतर सप्लाई करती हो, जैसा कि मुम्बई में हो रहा है।
- अनावश्यक बिजली की खरीद में कमी : वितरण कम्पनियां इस समय दिल्ली की जरूरत से ज्यादा बिजली खरीद रही हैं और अतिरिक्त बिजली की कीमत आखिरकार उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ रही है। सभी उपभोक्ता वितरण कम्पनियों द्वारा खरीदी जा रही इस अतिरिक्त बिजली के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त भुगतान कर रहे हैं और वे ऐसा करते रहेंगे। हम बिजली की इस अनावश्यक खरीद में कटौती करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव में कमी आएगी। कुल लागत को जोड़ने के बाद प्रति यूनिट प्रभावी वृद्धि 3.50 रुपये प्रति यूनिट रहेगी।
- प्रत्येक उपभोक्ता को अलग न्यूट्रल उपलब्ध कराना : बिजली के वर्तमान मीटरों में साझा न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से उपभोक्ता उस बिजली के लिए भी भुगतान कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वे नहीं कर रहे हैं। यह तथ्य सामने आया है कि निवासी बिजली की खपत किए बगैर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अधिक बिल का भुगतान रहे हैं। भाजपा प्रत्येक उपभोक्ता को अलग न्यूट्रल उपलब्ध कराएगी, जिससे बढ़े हुए बिलों में कमी आएगी।

- वितरण कम्पनियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना : वितरण कम्पनियों के कामकाज में पारदर्शिता का अभाव है। आज जहां एक ओर, डीईआरसी वैधानिक परामर्श में वर्ष 2013–14 के लिए बड़े नुकसान की सिफारिश कर रहा है और टैरिफ ऑर्डर में यह अतिरिक्त है। इसलिए उपभोक्ताओं के साथ विनियामक, वितरण कम्पनियों और दिल्ली सरकार द्वारा छल किया जा रहा है। इससे डीईआरसी और दिल्ली सरकार की विश्वसनीयता पर गम्भीर संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए भाजपा सीएजी लेखा परीक्षा के माध्यम से वितरण कम्पनियों के कामकाज में पारदर्शिता लाएगी।
- वितरण कम्पनियों के लिए प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। इससे कारगर ऊर्जा वितरण सुनिश्चित हो सकेगा।
- बिजली चोरी पर नियंत्रण : बिजली चोरी की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई आए दिन ऊर्जा के ऊंचे दामों के रूप में उपभोक्ताओं के माध्यम से कराई जाती है। इस प्रकार बिजली चोरी पर काबू पाकर हम बिजली के बिलों को कम कर सकेंगे।
- वितरण कम्पनियों को आरटीआई के दायरे में लाना : वितरण कम्पनियां आरटीआई कानून के दायरे में नहीं आतीं। भाजपा सरकार उन्हें आरटीआई कानून के दायरे में लाएगी, जो उन्हें आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाएगा तथा उनके कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी।
- डीईआरसी जवाबदेह : समय के साथ डीईआरसी (दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग) अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और विश्वसनीयता खो चुका है। हम योग्य लोगों को प्रमुख नियुक्त करके डीईआरसी को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो वितरण कम्पनियों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे।
- ऊर्जा लेखा परीक्षा कराएंगे : सभी हितधारकों द्वारा बिजली की खरीद, आपूर्ति और उसके इस्तेमाल में पारदर्शिता नहीं है, जिसकी वजह से वितरण कम्पनियों के पास बिजली संबंधी धोखाधड़ी करके बच निकलने की व्यापक सम्भावना है। ऊर्जा लेखा परीक्षा कराने से यह उलझन दूर होगी और बिजली के आम उपभोक्ता और उसका अधिक इस्तेमाल करने वाले का अंतर स्पष्ट होगा।

<u>शिक्षा</u>

- दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली के स्कूलों से 12वी पास करने वाले छात्र दिल्ली यूनिवार्सिटी में दाखिले से वंचित रह जाते हैं। हर राज्य में (सन ऑफ द सॉयल) लाभ मिलता है। हर साल दिल्ली के स्कूलों में 1.3 लाख छात्र 12वीं पास करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को ही डीयू में दाखिला मिल पाता है। ज्यादातर को दूसरे शहरों का रूख करना पड़ता है। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो दिल्ली से 12वीं पास करने वाले छात्रों का लिस्ट में 5 फीसदी अंकों की छूट दी जाएगी। ये छूट उन सभी कॉलेजों में लागू होगी, जिन्हें दिल्ली सरकार वित्तीय सहायता देती है। इतना ही नहीं, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी के सामने भी ऐसा ही प्रस्ताव रखेगी, ताकि दिल्ली के कॉलेजों में भी दिल्ली के छात्रों को 5 फीसदी अंकों की छूट मिल सके।

- दिल्ली में सत्ता में आने पर बीजेपी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने पर विशेष ध्यान देगी। झुग्गी–झोंपड़ियों और अवैध कालोनियों के पास नए स्कूल खोले जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को उचित संख्या में स्कॉलरशिप दी जाएगी।

बेहतर पुलिस

- दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पुलिस कर्मियों को आधुनिक उपकरण, आधुनिक वाहन और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की भर्ती बड़े पैमाने पर की जाएगी ताकि महिलाओं की सुरक्षा की समस्या को अच्छे से हल किया जा सके। इसके साथ ही मौजूदा महिला पुलिस कर्मियों को भी राहत मिलेगी। काम के बोझ तले महिला पुलिस कर्मियों का बोझ हल्का होगा।
- बीजेपी सुनिश्चित करेगी कि हर पुलिस स्टेशन में पर्याप्त महिला पुलिस कर्मी तैनात रहें।

दिल्ली को राज्य का दर्जा

- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2004 में संसद में विधेयक पेश किया था। दिल्ली पूर्ण राज्य विधेयक 2003 में तैयार किया गया ताकि नेशनल कैपिटल टैरिटरी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सके। लेकिन कांग्रेस ने उस समय विधेयक का विरोध किया और आज तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया।
- यदि हम केन्द्र और दिल्ली में सत्ता में आते हैं तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली के सम्पूर्ण विकास के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना आवश्यक है।

वैट को सरल बनाना

- मौजूदा वैट प्रणाली काफी जटिल है। व्यापारी टैक्स अधिकारियों की दया के भरोसे हैं। व्यापारियों, अफसरों की मनमानी के कारण व्यापारी परेशान रहते हैं। दिल्ली सरकार अनेक तरह के सर्कुलर जारी करती है, जिनका पालन लगभग असंभव है। बीजेपी वैट का सरलीकरण करेगी। वैट को व्यापारियों के लिए न्यायोचित बनाएगी ताकि व्यापारी भयमुक्त होकर टैक्स रिटर्न भर सकें।

घर का सपना करेगी सच

- हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सपना अपना घर होता है। बीजेपी आम इंसान के इस सपने को साकार करेगी। हाउसिंग नियमों का उदारीकरण किया जाएगा। निम्न और मध्यम वर्ग के लिए पर्याप्त संख्या में घर बनाए जाएंगे।
- दिल्ली के हर कोने में झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को घर दिया जाएगा । समयबद्ध तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर हर आम आदमी को घर।

कांग्रेस द्वारा पिछले 15 साल में लूट–खसोट का खुला खेल

भ्रष्टाचार

- कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70,000 करोड़ रूपए।
- यमुना सफाई घोटाला 3,000 करोड़ रूपए।
- बिजली निजीकरण में सीएजी ने 12,000 करोड़ रूपए के स्कैम का पर्दाफाश किया।
- वाटर सीवेज एंड सीवरेज डिस्पोजल इम्पलाइज यूनियन ने 200 करोड़ रूपए के घोटाले का पर्दाफाश किया। दिल्ली जल बोर्ड के भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निजीकरण के दौरान ये घोटाला हुआ।
- नकली राशन कार्ड घोटाला 257 करोड़ रूपए।
- 2008 दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय चुनाव प्रचार में 11 करोड़ रूपए के सरकारी फंड का दुरूपयोग। लोकायुक्त मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया।
- टैक्स छापे के दौरान शीला दीक्षित सरकार के मंत्री श्री राजकुमार चौहान ने एक निजी कम्पनी को बचाने के लिए पद का दुरूपयोग किया। (लोकायुक्त रिपोर्ट)
- कनॉट प्लेस सौन्दर्यीकरण योजना में 600 करोड़ का घोटाला।
- सरकारी स्कूलों के लिए कम्प्यूटर खरीद में 10 करोड़ रूपए का घोटाला।
- लो–फ्लोर बस खरीद में 130 करोड़ रूपए का घोटाला।
- सड़क निर्माण में 101 करोड़ रूपए का घोटाला।
- विदेशी लाइटों की खरीद में 225 करोड़ रूपए का घोटाला।
- स्ट्रीट लाईट खरीद में 31 करोड़ रूपए का घोटाला।
- मुद्रा स्फीति।
- पिछले दो वर्षों में जरूरी वस्तुओं के दाम में दोगुना बढ़ोत्तरी।
- पिछले चार साल में महंगाई दर का आंकड़ा 10 के अंक को पार कर गया। महंगाई ने समाज के हर वर्ग का बजट बिगाड़ दिया।
- फल और सब्जियां अब मध्यम और निम्न आय वर्ग की पहुंच से बाहर हो गई है। रसोई घर के बजट को काबू में रखने के लिए लोग अब रेडी–टू–ईट अपना रहे हैं। एसोसिएटिड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के सर्वे के अनुसार जहां आम व्यक्ति की आमदनी में 10 से 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं सब्जियों के दाम तो 250 से 300 फीसदी तक बढ़े हैं।
- ऐसोचैम का कहना है कि दामों में 88 फीसदी का इज़ाफा इतना ज्यादा है कि आम आदमी के लिए अपना घर चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है।

महंगाई

- पिछले दो वर्षों में जरूरी वस्तुओं के दाम में दोगुना बढ़ोत्तरी।
- पिछले चार साल में महंगाई दर का आंकड़ा 10 के अंक को पार कर गया। महंगाई ने समाज के हर वर्ग का बजट बिगाड़ दिया।
- फल और सब्जियां अब मध्यम और निम्न आय वर्ग की पहुंच से बाहर हो गई है। रसोई घर के बजट को काबू में रखने के लिए लोग अब रेडी–टू–ईट अपना रहे हैं। एसोसिएटिड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने हाल ही में कराए अपने सर्वेक्षण में ये जानकारी दी है। सर्वे के अनुसार हालांकि आम व्यक्ति की आमदनी में 10 से 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन सब्जियों के दाम 250 से 300 फीसदी तक बढ़े हैं।
- ऐसोचैम का कहना है कि दामों में 88 फीसदी का इज़ाफा इतना ज्यादा है कि आम आदमी के लिए अपना घर चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है।

बिजली

- देश के अन्य सभी राज्यों की तुलना में दिल्ली में बिजली की दरें सबसे ज्यादा बढ़ाई गई है। पिछले 15 साल में 30 फीसदी और पिछले दो साल में 72 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।
- दिल्ली सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोत्तरी करके निजी डिस्कॉम को दिल्ली के नागरिकों से 20,000 करोड़ रूपए वसूलने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरकार 300 फीसदी की बढ़ोत्तरी करनी पड़ेगी।
- निजी कम्पनियों ने जो मीटर लगाए हैं, उनसे तीन गुना ज्यादा बिल आ रहा है, जिससे दिल्ली के उपभोक्ताओं को 2000 करोड़ रूपए ज्यादा अदा करने पड़ेंगे।
- बिजली के निजीकरण के समय 2005 में शीला दीक्षित सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि दिल्लीवासी अपना पावर सप्लायर खुद चुन सकते हैं और बिजली की दरें घटा दी जाएंगी, लेकिन क्या हुआ ?
- निजी बिजली कम्पनियों का कैग से ऑडिट क्यों नहीं कराया जाता।

पानी

- आधी दिल्ली को दिल्ली जल बोर्ड का पानी नसीब नहीं होता। टैंकरों से पीना पड़ता है।
- 15 साल के शासन में शीला दीक्षित सरकार ने पानी की दरों में 1100 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है।
- दिल्लीवासियों को पानी मय्यसर नहीं होता, इसलिए मौके का फायदा उठाने के लिए वाटर टैंकर माफिया पनपा।
- मुम्बई जैसे महंगे शहर से भी 9 गुना ज्यादा है, दिल्ली के पानी की दर।
- साल 2013 की अपनी रिपोर्ट में कैग ने लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड पानी की भारी बर्बादी करता है। तीन साल में दिल्ली सरकार को 3,950 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ, क्योंकि कुल वाटर सप्लाई की केवल 40 फीसदी सप्लाई के ही बिल भेजे गए। यानी 60 फीसदी पानी सप्लाई के बिल ही नहीं बनाए गए।

- पानी के बिल की दरें बेतहाशा बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार ने 2010 से प्रावधान रखा कि हर साल पानी की दर में 10 फीसदी की वृद्धि हो जाए। इस बार चुनावी साल में बढ़ोत्तरी नहीं की गई, लेकिन याद रहे नियम रद्द नहीं किया गया है यानी भविष्य में दाम बढ़ेंगे।
- मुनक नहर निर्माण पर 478 करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च किए गए, लेकिन दिल्ली को अब तक इस नहर से एक बूंद पानी हरियाणा से नहीं मिला है। जबकि हरियाणा व केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है।
- दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कुप्रबंधन के शिकार हैं और अपनी तय क्षमता का केवल आधा यानी 50 फीसदी काम करते हैं।
- 2012 में दिल्ली जल बोर्ड से लिए गए पानी के नमूनों में से 80 फीसदी शुद्धता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे।
- 1634.8 करोड़ रूपए की भारी लागत से 2007–12 के बीच 900 किलोमीटर की सीवर लाईन बिछवाई गई, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली जल बोर्ड केवल एक एमजीडी अतिरिक्त पानी ही दे पाया और ग्रांट को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया। 2010–11 में 100 फीसदी ग्रांट और 2011–12 में 51 फीसदी ग्रांट इस्तेमाल नहीं कर पाया।
- पानी का मैनेजमेंट ठीक नहीं। दिल्ली में सब जगह पाईप लाइन नहीं बिछी तो जनता को पानी कैसे मिलेगा ?
- कच्चे पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए 1994 में यमुना नदी पर दो बांध बनाने का प्रावधान रखा गया था। 18 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है, जबकि 214 करोड़ रूपए से ज्यादा का खर्च हो चुका है।

स्वास्थ्य

- आरटीआई आवेदन के माध्यम से मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डीएसएचएम) के तहत आवंटित 31,069.13 रुपयों में से वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान महज 28.9 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया।
- निम्नलिखित आंकड़े दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होने के कांग्रेस के दावों की पोल खोल देते हैं, क्योंकि इनमें दर्शाया गया है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित धन को खर्च ही नहीं कर सकी।

गतिविधि उपयोग	स्वीकृत बजट	प्रतिशत खर्च
मातृ स्वास्थ्य	23.14 करोड़ रुपये	10.3 प्रतिशत
बाल स्वास्थ्य	4.25 करोड़ रुपये	5.75 प्रतिशत
परिवार नियोजन	4.39 करोड़ रुपये	24.7 प्रतिशत
नव–निर्माण/मरम्मत	45.92 करोड रुपये	3.24 प्रतिशत
मोबाइल मेडिकल यूनिट	46.45 लाख रुपये	0.0 प्रतिशत

- दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों और चिकित्सकों की उपलब्धता की दर बहुत निराशाजनक है। दिल्ली में प्रति एक हजार व्यक्तियों पर महज 2.5 बिस्तर हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार, प्रति एक हजार व्यक्तियों पर 5 बिस्तर होने चाहिये।
- बीमा योजना के तहत महज 3578 बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है। इस पर महज 4.39 लाख रुपये खर्च किये गए हैं।
- दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, वास्तविकता यह है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता निशानजनक रूप से कम है। यहां प्रति 10,000 व्यक्तियों पर 2 से भी कम क्लीनिक्स हैं।
- वर्ष 2013 की सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग की एम्बोलेंसों का या तो दुरुपयोग गया जाता है या फिर उनका इस्तेमाल ही नहीं होता, और तो और उनमें बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। दिल्ली में 100 कैट एम्बुलेंस भी नहीं।
- ऑडिटर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहर के कई अस्पतालों में बहुत सी आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। शुद्ध, स्वच्छ पेय जल की सुविधा का अभाव है।
- वर्ष 1997 और 2008 के बीच आवंटित 60–700 बिस्तरों के अस्पतालों की क्षमता वाले 10 अस्पतालों की जमीन पर अब तक निर्माण कार्य ही शुरू नहीं हुआ, केवल शिलान्यास हुआ।
- द्वारका में (750 बिस्तर), विकासपुरी में (200 बिस्तर), मादीपुर में (200 बिस्तर), ज्वालापुरी में (200 बिस्तर), अम्बेडकर नगर में (200 बिस्तर) के अस्पतालों के निर्माण में पहले ही काफी देरी हो चुकी है।
- द्वारका में (750 बिस्तर), विकासपुरी में (200 बिस्तर), मादीपुर में (200 बिस्तर), ज्वालापुरी में (200 बिस्तर), अम्बेडकर नगर में (200 बिस्तर) के अस्पतालों के निर्माण में पहले ही काफी देरी हो चुकी है।
- एक चौंका देने वाली कमी के रूप में यह पाया गया कि 5 अस्पतालों में ब्लड बैंक्स् नहीं हैं, जबकि जीटीबी अस्पताल के ब्लड बैंक के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया है।
- दिल्ली सरकार ने 2900 बिस्तरों की क्षमता वालें 12 नए अस्पताल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो सका।

शिशु मृत्यु–दर

- शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के दिल्ली सरकार के दावों के बावजूद, एक आरटीआई आवेदन से पता चला है कि पिछले 5 वर्षों में शहर के अस्पतालों में 50,000 शिशुओं की मृत्यु हुई।
- इसका आशय यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में हर साल औसतन 10,000 शिशुओं की मृत्यु होती है।

अस्पताल में ईडब्ल्यूएस

- कांग्रेस सरकार का दावा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों (ईडब्ल्यूएस) का निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाता है।
- हकीकत कुछ और है। और तो और सरकार के अपने रिकॉर्ड के अनुसार यह स्पष्ट है कि चिन्हित किये गए 43 निजी अस्पतालों में से कम से कम 34 ईवीएस मरीजों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराने के नियमों का पालन नहीं करते हैं।

शिक्षा

- दिल्ली की आबादी हर साल चार से पांच लाख बढ़ती है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने 80 सरकारी स्कूल बन्द कर दिए।
- दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों के 12,000 पद खाली पड़े हैं।
- ज्यादातर सरकारी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है।
- स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी हैं।
- शिक्षा के अधिकार के तहत सरकारी स्कूलों की हर क्लास में 30 छात्रों के लिए एक टीचर होना चाहिए और हर क्लास में 80 से 100 बच्चे होने चाहिए।
- शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ प्रथम और बीजेपी के एक सर्वे के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाते। स्तर बहुत ही खराब है।
- अध्यापकों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। 30 फीसदी अध्यापक साल भर नॉन टीचिंग कामों में लगे रहते हैं, उनसे क्लर्कों की तरह काम लिया जाता है।
- पब्लिक स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत नीचे है।

उच्च शिक्षा

- दिल्ली सरकार की ओर से पिछले 15 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई नया कॉलेज नहीं जोड़ा गया। कॉलेजों में सीटें पिछले कई सालों से 54000 ही है।
- दिल्ली के ज्यादातर छात्र, कॉलेजों की कमी के कारण डीयू के कॉलेजों में दाखिला पाने में नाकाम रहते हैं। कांग्रेस सरकार का दावा है कि दिल्ली में उच्च शिक्षा सुविधाएं और वातावरण में सुधार हुआ है।
- लेकिन, हकीकत यह है कि दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है।

लाडली योजना

- कांग्रेस सरकार का दावा है कि लाडली योजना से 5.8 लाख लड़कियां लाभान्वित हुई हैं।
- लेकिन सीएजी ने इस दावे की कलई खोल दी है। सीएजी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार करीब 42 प्रतिशत नामांकित लड़कियां योजना से हट चुकी है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2010–12 में 125,808 मामलों का नवीकरण लंबित था, लेकिन महज 73,108 मामलों (यह महज 58.11 प्रतिशत है) का ही नवीकरण किया जा सका।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए शिक्षा

- कांग्रेस सरकार का दावा है कि ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले छात्र निजी स्कूलों के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- लेकिन वास्तविकता यह है कि दिल्ली सरकार के बढ–चढ़ कर किये गये दावों को एडजेस्ट करने के बाद भी हर साल 15000 सीटें निजी स्कूलों में खाली रहती हैं और इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

लोक निर्माण विभाग की सड़कें

- दिल्ली सरकार ने बदतर रख–रखाव का हवाला देते हुए एमसीडी से लगभग 673 सड़कें अपने कब्जें में ले ली थी। सभी सड़कें 60 मीटर चौड़ी थीं, लेकिन कहना न होगा सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है।
- फरवरी 2013 में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 1800 करोड़ रूपया खर्च करके सड़कों की मरम्मत की जाएगी, लेकिन बरसात में कथनी और करनी का अंतर साफ पता चल गया। सड़कों में गड्ढे हैं, उनमें पानी भरा रहता है।
- नांगलोई के जलेबी चौक की सड़कों पर भी 12.33 करोड़ रूपए खर्च करने की घोषणा की गई, लेकिन अब तक हालात जस के तस हैं।
- यमुना के वजीराबाद पुल पर सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण कार्य में हो रही लगातार देरी के कारण लागत कई सौ करोड़ रूपए बढ़ गई है।

कानून और व्यवस्था

- मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी है, तो कोलकाता सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ इंडिया है। दिल्ली वालों के लिए इससे बढ़कर शर्मिन्दगी और क्या हो सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार को ये तमगा हमने और आपने नहीं नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिया है। क्या कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े जरा गौर से पढ़िए –
  - भारत के 50 मुख्य शहरों में होने वाली बलात्कार की घटनाओं में से हर पांचवी घटना दिल्ली में घटती है।
  - 2012 में देश के 53 मुख्य शहरों में बलात्कार के 3025 केस दर्ज किए गए। इनमें 19.34 फीसदी केस केवल दिल्ली के हैं। जबकि 2011 में ये दर 17 फीसदी थी।
  - दिल्ली में महिलाओं के प्रति छेडछाड़ की घटनाओं में 700 प्रतिशत, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के मामलों 495 प्रतिशत व बलात्कार के मामलों में 240 प्रतिशत की वृद्धि पिछले एक वर्ष में हुई है।
- एनसीआरबी के आंकड़े और भी बहुत कुछ कहते हैं। दिल्ली पुलिस को 2012 में फोन पर (जिसमें 100 नंबर भी शामिल है) और लिखित में 20,99,170 शिकायतें मिलीं, लेकिन मुकदमों में केवल 60,397 ही तब्दील हो पाई। जबकि महाराष्ट्र में 94, 3994 शिकायतों में से 3,33 680 के केस में तब्दील किया गया।

अपने घर का सपना

- गरीबों के लिए अपने घर का सपना सपना ही बना रहा। मुख्यमंत्री ने राजीव रत्न आवास योजना के तहत कम लागत के 60,000 फ्लैट देने का वायदा किया था, लेकिन अब तक केवल 14,000 घर ही बन पाए हैं। वो भी पूरे नहीं बने, अभी निर्माण कार्य जारी है और अब तक किसी एक व्यक्ति को कभी घर आवंटित नहीं किया गया है।
- औद्योगिक मजदूरों के लिए डीएसआईआईडीसी ने 2007 में 7000 घर देने की घोषणा की थी, लेकिन नरेला और बवाना में अब तक मात्र 1500 घर ही बनाए गए हैं।
- दिल्ली की आबादी का 40 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा अपने घर के लिए तरस रहा है।
- पिछले विधानसभा चुनाव से पहले 1639 अवैध कालोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किए गए, लेकिन सभी नकली थे, इसलिए रद्द करना पड़ा।
- अवैध कालोनियों के ले–आउट प्लान के खर्च का बोझ उठाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पर गैर–न्यायोचित शर्तें लगा दी।
- दिल्ली सरकार ने इन कालोनियों में एमसीडी को विकास कार्य करने की अनुमति नहीं दी और पार्षद फंड का प्रयोग करने पर पाबंदी भी लगा दी।
- पिछले 15 वर्षों में अवैध कालोनियों में कोई विकास कार्य नहीं किया गया।
- कागजों पर कालोनियां नियमित हो रही हैं। इन पर न लोन, न नक्शे पास हो सकते हैं और न ही इनकी रजिस्ट्री खोली गई है।

दिल्ली शहर के गांव

- पिछले 15 साल में लाल डोरा का विस्तार नहीं किया गया।
- कांग्रेस ने अपने घोषणा–पत्र में वायदा किया था कि दिल्ली भूमि सुधार कानून की धारा 81 समाप्त होगी, लेकिन 15 साल होने को आए, ये महज़ चुनावी वायदा ही रहा।
- लाल डोरा विस्तार को भी घोषित नहीं किया गया।
- गांव के रिहायशी और व्यापारिक इलाकों को नियमित किया जाना चाहिए।
- गांवों में बेसमेंट एवं तीन मंजिलों के निर्माण के लिए अनुमति लेने का नियम खत्म किया जाना चाहिए।
- दिल्ली के अनेक गांववासियों के पास रोजी–रोटी के साधन नहीं है।
- खेती–बाड़ी के लिए किसानों को कुएं खोदने और ट्यूब वैल लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- दिल्ली के ज्यादातर गांवों में सीवेज और वाटर सप्लाई सुविधा नहीं है।
- दिल्ली के गांवों में परिवहन सुविधा नहीं है।
- भाजपा के शासनकाल में गांवों में जो विकास केन्द्र स्थापित किए गए थे, उनका कांग्रेस शासन में नामो–निशान भी नहीं है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्त्ति

- गरीबी रेखा से ऊपर 15.85 लाख से अधिक कार्डधारियों को सब्सिडाईज्ड अनाज नहीं मिलता है। (गौर करें कि इनके कार्डों पर मोहर नहीं लगाई गई।)
- गरीबी रेखा से ऊपर 11.53 लाख मोहरशुदा कार्डधारकों की भी यही शिकायत है। (एपीएल कार्डधारक को महीने मं 25 किलो अनाज और दस किलो चावल हर महीने मिलना चाहिए।)
- अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 1.57 लाख परिवारों को अन्न दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 1.01 लाख परिवारों को ही इसका लाभ मिला। यानी 0.56 लाख परिवार योजना के लाभ से वंचित रहे। योजना के लिए निर्धारित राशि का इस्तेमाल भी नहीं किया गया।
- 257 करोड़ रूप्ए के नकली राशन कार्ड घोटाले का पर्दाफाश हुआ।
- अन्नपूर्णा योजना का लाभ अब तक बहुत कम परिवारों को मिला है।
- दिल्ली अन्नश्री योजना का दिल्ली सरकार बढ़–चढ़कर श्रेय लेती है। सरकार का दावा है इस योजना का लाभ एक सलाख से ज्यादा लोागों को पहुंच रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल 8000 लोग ही अन्नश्री योजना का लाभ उठा पाए हैं। 600 रूपए में क्या परिवार का गुजारा हो सकता है ?
- दिल्ली में खाद्य एवं आपूर्त्ति विभाग में 1100 पद हैं। इनमें से आधे से ज्यादा खाली पड़े हैं।
- दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन जैसे पीएसयू दिल्लीवासियों को जरूरत की खाद्य सामग्री मुहैया कराने के बजाए शराब बेचने में ज्यादा व्याप्त है।
- राजधानी दिल्ली में लगभग 30 फीसदी राशन कार्ड नकली हैं। इन कार्डों पर लिया गया चावल, चीनी, गेहूं और अन्य सामान खुले बाजार में बेच दिया जाता है।
- दिल्ली का पीडीएस सिस्टम सबसे भ्रष्ट है।

खाद्य सुरक्षा

- दिल्ली सरकार ने बड़े–बड़े विज्ञापन लगाए कि दिल्ली में अब कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। 15 साल तक इन गरीबों की याद नहीं आई। चुनाव के तीन महीने पहले क्यों खाद्य सुरक्षा बिल लाया गया ?
- सरकार कहती है कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश दिल्ली के 73.5 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अपने 15 साल के राज में दिल्ली सरकार शहर की कुल आबादी 1.67 करोड़ मं से आधी जनता को भी खाद्य सुरक्षा नहीं दे पायी।
- सूचना के अधिकार के तहत खाद्य सुरक्षा पर कांग्रेस के दोहरे मानदंडों की कलई खुली है।
- सूचना के अधिकार के तहत दायर एक याचिका के जवाब में पता चला है कि अन्नश्री योजना के तहत अब तक केवल 7220 लोगों को ही लाभ पहुंचा है। जबकि सरकार बढ़ा–चढ़ाकर गुणगान कर रही है आर दावा कर रही है कि 5,74,428 लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है।
- लगभग दो करोड़ की आबादी वाले दिल्ली शहर में केवल 2500 लोक वितरण प्रणाली केन्द्र हैं।

अनधिकृत कालोनियां

- दिल्ली सरकार अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 50 लाख लोगों के साथ अब तक छलावा कर रही है। एक नज़र में देखिए :–
  1. 1639 कुल अनधिकृत कालोनियां है।
  2. 1210 को झूठे प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिए गए।
  3. 895 की घोषणा की कि इनको नियमित करेंगे।
  4. 584 को नियमित नहीं किया कि आधी या पूरी सरकारी जमीन पर बनी हैं।
  5. 312 नियमित को नियमित करने की केवल घोषणा की। वो भी तब जब आरडब्ल्यूए 50,000 रूपए प्रति एकड़ जमा करा देंगी, तब होंगी।
- आज तक एक भी कालोनी नियमित नहीं हुई।
- इन कालोनियों पर न तो लोन मिल सकता है, न रजिस्ट्री हो सकती है और न ही नक्शे पास हो सकते हैं।
- कालोनियों में विकास के कार्य के नाम पर बिना सीवर डाले ही सड़कें बनाई गई हैं।
- पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने सैकड़ों अनधिकृत कालोनियों के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों को प्रॉविजनल रेगुलराइजेसन सर्टिफिकेट बंटवाये थे। ये प्रमाणपत्र कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा बांटे गये थे।

झुग्गी–झोपड़ी कलस्टर

- कांग्रेस सरकार ने गरीब लोगों के लिए 14,844 फ्लैटों के निर्माण का दावा किया है लेकिन उसने झुग्गी–झोपड़ी वालों को यह नहीं बताया कि उसने 60,000 फ्लैटों का वायदा किया था।
- लाभार्थियों को अभी तक कोई भी फ्लैट नहीं दिये गये हैं।
- दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट (डीएचडीआर) 2013 में कहा गया है कि झुग्गी–झोपड़ी कलस्टरों में रहने वाले लोगों में से आधे से अधिक के पास अपने घर में शौचालय की सुविधा नहीं है और उन्हें बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। इसके कारण महिलाओं और बच्चों को अपराध और बीमारी का खतरा रहता है।
- वर्ष 1993 और 1998 के बीच भाजपा शासन के दौरान प्रत्येक झुग्गी–झोपड़ी कलस्टर में बस्ती विकास केन्द्र था जहां उन्हें कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था थी जिससे कि उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। इन केन्द्रों का उपयोग समुदाय केन्द्र के रूप में भी किया जाता था जहां विवाह और अन्य सामुदायिक कार्यक्रम तथा त्यौहार आदि मनाये जाते थे।
- यूडीएचआर के परशेप्सन सर्वे के अनुसार झुग्गी–झोपड़ी कलस्टरों और इसी प्रकार की अन्य बस्तियों में बिजली की अनियमित सप्लाई, भारी भरकम बिजली के बिल आना सामान्य समस्या है।

मैली यमुना

- भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पावन नदी यमुना प्रदूषण और कचरे के कारण दम तोड़ रही है। यमुना गंदे नाले मं तब्दील हो गई है। 15 साल के शासन काल में शीला सरकार ने 3000 करोड़ रूपए खर्च किया लेकिन यमुना मैली की मैली ही रही।
- यमुना के कुल प्रदूषण में दिल्ली और आगरा का 90 फीसदी योगदान है।
- दिल्ली की 40–50 फीसदी आबादी ऐसे इलाकों में रहती है, जहां सीवरेज नहीं है और इनका मैला सीधे यमुना में जाता है।
- दिल्ली में कितना सीवेज बनता है, इसके ठोस और प्रमाणित आंकड़ें नहीं हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अनुमान के अनुसार 2,900 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, जबकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि दिल्ली की नालियों से 3,684 मिलियन लीटर मैला प्रतिदिन आता है।

यूपीए सरकार के काल में मुख्य घोटाले

- रेलवे प्रमोशन स्कैम 2013
- कोयला घोटाला (2012–1855.91 विलियन)
- डीआईएएल घोटाला – 1.63 लाख करोड़
- अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्कैम – केन्द्र सरकार ने 290.33
- टूजी स्पैक्ट्रम घोटाला (2010) 1.76 लाख करोड़
- कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला – 70,000 करोड़ रूपए

बेरोजगारी

- दिल्ली सरकार का दावा है कि बेरोजगारी दर कम हुई है, लेकिन कांग्रेस के अपने ही आंकड़ों के अनुसार 15 साल में बेरोजगारी के आंकड़ों में केवल दो लाख की ही कमी कर पाई है और इन्हीं में रेहड़ी–पटरी वाले, रिक्शा चालक भी शामिल है।
- जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 15 साल में बेरोजगारी दर बढ़ी है। कांग्रेस जान–बूझकर तथ्य छिपा रही है। 1999–2000 में बेरोजगारी दर 3.6 फीसदी थी, जबकि अब 4.0 फीसदी है।
- पिछले 10 साल में रोजगार ब्यूरो में केवल 11242 लोगों को रोजगार दिलवाया, जबकि 1016328 लोगों ने ब्यूरो में अपना नाम दर्ज करवाया था।
- दिल्ली सरकार में पिछले दस साल में 91585 पद खाली हुए। इनमें से ..... अब भी खाली पड़े हुए हैं।

बजट

- दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।
- कैग ने सरकार के दावे की हवा निकाल दी है।
- कैग के अनुसार बदतर प्लानिंग और अपर्याप्त टैक्स वसूली के कारण दिल्ली सरकार को 2700 करोड़ रूपए का राजस्व घाटा हुआ है।
- टैक्स वसूली के तरीकों में कमियां छूट के अनियमित दावों के कारण दिल्ली सरकार को 2310 करोड़ रूपए कम टैक्स मिला, इसमें 404 करोड़ रूपए का ब्याज भी शामिल है।

परिवहन

- कांग्रेस सरकार का यह दावा है कि उसने परिवहन व्यवस्था में सुधार किया है।
- किन्तु सच्चाई यह है कि डीटीसी की बेड़े की आधी बसें ब्रेक डाउन और घटिया रख रखाव के कारण डिपो में खड़ी हैं। इससे डीटीसी को भारी नुकसान हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 2011–12 में 2,335.13 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।
- कांग्रेस सरकार मोनो रेल की बात करती है किन्तु उसने स्वयं स्वीकार किया है कि यह काम 2017 से पहले शुरू नहीं हो सकता। सरकार ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है और सब कुछ कागजों पर ही है।
- कांग्रेस सरकार दिल्ली में सीएनजी परिवहन शुरू करने का श्रेय लेती है जबकि सच्चाई यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक वाहनों में सीएनजी के प्रयोग का आदेश दिया था।
- कांग्रेस सरकार ने परिवहन विभाग में कुप्रबंधन ही नहीं किया बल्कि परिवहन घोटाला भी किया जिसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री लिप्त थे।
- लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों का रख रखाव उचित रूप से नहीं किया जा रहा है और सीएजी ने इसके लिए लोक निर्माण विभाग की कड़ी आलोचना की है।
- कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसने डीटीसी की बेड़े में 1700 बसों का इजाफा किया है किन्तु अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
- डीएचडीआर 2013 के परशेप्सन सर्वे के अनुसार दिल्ली के दो तिहाई लोगों ने बताया कि उनके इलाकों में सड़कों की स्थिति बदतर है।
- झुग्गी–झोपड़ी कलस्टरों और अनधिकृत कालोनियों में सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है जहां कालोनियों के अंदर वाली सड़कों की उचित मरम्मत नहीं होती और स्ट्रीट लाइटें भी नहीं जलतीं।

पर्यावरण

- कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसने दिल्ली में पर्यावरण में सुधार किया है।
- किन्तु दिल्ली अभी भी देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है।
- डीएचडीआर के अनुसार दिल्ली में वन क्षेत्र घटा है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा करवाये गये अध्ययन में यह पाया गया है कि दिल्ली "हाई हेल्थ रिस्क" जोन में आता है। जिसका यह अर्थ है कि आउट डोर पार्टीकुलेट मैटर में खतरनाक रूप से वृद्धि हुई है।
- दिल्ली की आबादी पिछले 10 वर्षों में 21 प्रतिशत बढ़ी है और यह जारी है।
- कांग्रेस सरकार ने 3,000 करोड़ रूपये का यमुना नदी सफाई घोटाला किया है।
- पिछले 15 वर्षों में हजारों करोड़ रूपये खर्च करने के बावजूद कांग्रेस सरकार यमुना को साफ करने में असफल रही है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा ही दिल्ली में सीएनजी का प्रयोग शुरू कराया गया था।

समाज कल्याण

- कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसने 14 लाख बुजुर्गों को लाभ पहुंचाया है जबकि वह केवल 4 लाख बुजुर्गों को ही पेंशन देती है।
- कांग्रेस सरकार का दावा है कि वह जन आहार केन्द्रों से 15 रूपये में "हेल्दी फूड" देती है। सच्चाई यह है कि यह खाना हेल्दी नहीं है और चूंकि यह योजना वर्ष 2010 में शुरू की गई थी इसकी गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आई है। हजारों लोगों ने विशेषरूप से दिहाड़ी मजदूरों ने शिकायत की है कि प्रति प्लेट भोजन की मात्रा भी कम हो गई है।
- लगभग 50,000 गृहविहीन लोग अभी भी दिल्ली की सड़कों पर रहते हैं।
- डीएचडीआर 2013 के परशेप्सन सर्वे में कहा गया है कि अनधिकृत कालोनियों में 70 प्रतिशत और झुग्गी झोपड़ी कलस्टरों की आधी आबादी ने बताया कि जल उपलब्धता की मात्रा उनके क्षेत्र में औसत से कम है।

अल्पसंख्यकों की स्थिति

- मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति का अध्ययन करने वाली सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कांग्रेसी शासित राज्यों ने मुसलमानों की खराब स्थिति बताई गई है। न उनके लिए शिक्षा के अवसर हैं और न ही रोजगार के। यह कमेटी मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी।
- इसी कमेटी ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा जैसे भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों की स्थिति काफी बेहतर बताई है।
- दिल्ली में भी हम अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। उनकी शिक्षा और रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उनको विकास में बराबर का भागीदार बनाया जाएगा।

दिल्ली में बहेगी
अब हवा बदलाव की

भाजापा आयेगी
दिल्ली मुस्कुरायेगी

14 Pandit Pant Marg, New Delhi - 110001
011-23712323 or 011-23712744
www.bjpdelhi.org, info@bjpdelhi.org

/BJPDelhi /BJPDelhiState /BJPDelhiState

Join us with Missed Call : 011-66-57-5555